

## भारत तथा दक्षिण अफ्रीका ने WTO से की ई-कॉमर्स नियमों की पुनः जाँच की मांग

### चर्चा में क्यों?

ई-कॉमर्स के क्षेत्र में अग्रणी अमेज़न, अलीबाबा और वॉलमार्ट कंपनियों के बीच भारतीय बाज़ार के लिये जारी प्रतिस्पर्धा को देखने के बाद भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक सामानों के संचरण पर सीमा शुल्क को लागू नहीं करने के मौजूदा नियमों को जारी रखना उचित है अथवा नहीं।

### प्रमुख बिंदु

- 12 जुलाई, 2018 को विश्व व्यापार संगठन में भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा प्रसारित एक संयुक्त प्रस्ताव में कहा गया है कि 1998 में प्रचलित वास्तविकताओं में दो दशक बाद महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।
- दोनों विकासशील देशों (भारत और दक्षिण-अफ्रीका) के अनुसार "ये परिवर्तन," विकास के दृष्टिकोण से विशेष रूप से राजकोषीय पक्ष पर अस्थायी अधस्थगन (Temporary Moratorium) के प्रभावों की पुनः जाँच की आवश्यकता को दर्शाते हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के संचरण (जिसमें शुरुआत में केवल ई-बुक, संगीत और वभिन्न प्रकार की सेवाओं जैसे "डिजिटलीकृत उत्पादों" को शामिल किया गया था) में कई गुना वृद्धि को देखते हुए, सभी मुद्दों की पुनः जाँच करना आवश्यक है।
- इससे पहले, इंडोनेशिया ने भी WTO के ब्यूनस आयर्स मंत्रसितरीय बैठक में इलेक्ट्रॉनिक संचरण पर अधस्थगन की नरितरता का वरिध कया था, जिसमें तर्क दया गया था कि इसका असर सीमा शुल्क और घरेलू कंपनियों पर पड़ा है।

### दोनों देशों द्वारा दया गया तर्क

- दोनों देशों द्वारा दया गया तर्क यह था कवर्तमान में जनि वस्तुओं का व्यापार इलेक्ट्रॉनिक संचरण के माध्यम से कया जा रहा है, उन पर सीमा शुल्क अधस्थगन के परणामस्वरूप राजस्व में अधक हानि होगी।
- अमेरिका के नेतृत्व में प्रमुख औद्योगिक देशों सगिपुर, कोरया और हॉन्गकॉन्ग जैसे कई विकासशील देशों द्वारा मांग की गई क अस्थायी अधस्थगन को स्थायी बनाया जाए ताक यह इंटरनेट के माध्यम से सामानों के कारोबार को सुनश्चित कर सके।

### 1998 से लागू है इलेक्ट्रॉनिक संचरण पर सीमा शुल्क न लगाने का नयिम

- 1998 से WTO के सदस्य इलेक्ट्रॉनिक संचरण पर सीमा शुल्क को लागू नहीं करने पर सहमत हैं।

### अमेरिका का तर्क

- इससे पहले प्रसारित एक प्रस्ताव में अमेरिका द्वारा यह तर्क दया गया क इस समझौते के अंतर्गत अनविरय रूप से डिजिटल उत्पादों को शुल्क मुक्त करने की आवश्यकता है।
- अमेरिका का मानना है क व्यापार नयिमों द्वारा यह सुनश्चित कया जा सकता है क सरकारें डिजिटल उत्पादों पर सीमा शुल्क न लगाने की प्रकरया जारी रखें या इस प्रकरया को बंद कर दया जाए।
- अमेरिका ने सूचनाओं के मुक्त प्रवाह, मालकाना सूचना की सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा, इंटरनेट सेवाओं को सुवाधाजनक बनाने, प्रतिस्पर्धी दूरसंचार बाजारों और डिजिटल माध्यमों के माध्यम से व्यापार सुवाधा के लिये अधिकतमतम "इलेक्ट्रॉनिकस वाणजिय पहल" (Electronic Commerce Initiative) का प्रस्ताव भी दया।
- यूरोपीय संघ और अन्य औद्योगिक रूप से उन्नत तथा विकासशील देशों द्वारा अमेरिका के एजेंडे को भी प्रतिबिंबित कया गया है।

### चीन, उदारीकरण के नयिमों का प्रबल समर्थक

- चीन इलेक्ट्रॉनिक वाणजिय को नयितरित करने वाले नयिमों के महत्वाकांक्षी उदारीकरण का एक मजबूत समर्थक भी है।
- इस पृष्ठभूमि के वपिरित भारत और दक्षिण अफ्रीका के संयुक्त प्रस्ताव ने ई-कॉमर्स अधस्थगन से संबंधित मुद्दों की पुनः परीक्षा और पुनर्मूल्यांकन की मांग की है और इन मांगों को कई विकासशील और गरीब देशों द्वारा समर्थित कया जा रहा है।

